उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग

बनाम

एल.आई. पारिजा और अन्य.

16 जनवरी 2006

[अरिजीत पासायत और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226-रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश, आयोग को फिक्सिन, टैरिफ से रोकना-बाद में, आदेश वापस ले लिया गया लेकिन मेलर्स को लंबित रखा गया- माना गया, रोक आदेश बचाव योग्य नहीं हैं - इसके अलावा, इस बीच आयोग ने टैरिफ और लेवी तय कर दी है, रिट याचिकाओं को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो निष्फल हो गए हैं - अंतरिम आदेश - उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1994।

वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें अपीलकर्ता को वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए टैरिफ तय करने के लिए आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इस बीच, उच्च न्यायालय ने हालांकि पहले के आदेशों को वापस ले लिया लेकिन अपीलकर्ता की कार्रवाई की निगरानी के उद्देश्य से रिट याचिकाओं को लंबित रखा।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को उसके कार्य करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश बचाव योग्य नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को आवश्यक निर्णय लेने की अनुमति देने के बाद, आयोग ने वास्तव में निर्णय लिया और प्रासंगिक अवधि के लिए टैरिफ तय किया; और उसी हिसाब से लेवी बनाई जा रही है. निर्धारित टैरिफ की शुद्धता पर निर्धारित फोरम के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है, जैसा कि उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1994 में प्रदान किया गया है। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय के लिए रिट याचिकाओं को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन अपीलों में उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं को निष्फल मानने का निर्देश देने के अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। [421-एफ-एच; 422-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या 519-524/2006

(विविध मामले संख्या 7410 और 8953/2002 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 3.2.2003 के निर्णय और आदेश से, विविध मामले संख्या 414/2003 में दिनांक 7.3.2003 और O.J.C.No में

दिनांक 14.3.2003 से 6751/2001 एवं विविध प्रकरण संख्या 414 और 580/2003)

अपीलकर्ताओं के लिए श्री राज कुमार मेहता।

प्रतिवादियों की ओर से जनरंजन दास, श्वेतकेतु मिश्रा, आर.के.तलवार, अमिल तलवार, यशपाल ढींगरा और सुश्री.एन.अन्नपूर्णानी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पासायात, जे.

पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

अनुमति दी गई।

अपीलें अनिवार्य रूप से उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई थीं, जिसमें उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में 'आयोग') पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था- अपीलकर्ता यहां 2002-03 और 2003-04 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में कदम उठा रहा है। सुनवाई के दौरान,

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विविध मामले संख्या 1380 और 1805/2003 में दिनांक 02.09.2003 का एक आदेश हमारे सामने रखा, जिसके द्वारा पहले के आदेशों को संशोधित किया गया था और आयोग को उपरोक्त दो अवधियों के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रश्न पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता, जो इन अपीलों में प्रतिवादी संख्या 2 से 13 हैं, नोटिस की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं। दिनांक 02.09.2003 के आदेश से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने आयोग की शक्ति के प्रयोग पर रोक के आदेश को वस्तुतः वापस ले लिया। लेकिन साथ ही, उच्च न्यायालय ने आयोग की कार्रवाई की निगरानी के उद्देश्य से मामलों को लंबित रखा है। हमें ये आदेश काफी अजीब लग रहे हैं. आयोग को अपने कार्य करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश बचाव योग्य नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को आवश्यक निर्णय लेने की अनुमति देने के बाद, आयोग ने वास्तव में निर्णय लिया है और दो अवधि के लिए टैरिफ तय कर दिया है। यह भी विवादित नहीं है कि लेवी निर्धारित टैरिफ के आधार पर लगाई जा रही है। यह विवाद में नहीं है कि निर्धारित टैरिफ की शुद्धता पर निर्धारित फोरम के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है जैसा कि उड़ीसा विद्युत सुधार में प्रदान किया गया है। -{अधिनियम.1994. ऐसा होने पर उच्च न्यायालय के लिए रिट याचिकाओं को लंबित रखने की

कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि आयोग पहले ही निर्णय ले चुका है, टैरिफ तय कर दिए गए हैं और शुल्क लगाए जा रहे हैं, इसलिए इन अपीलों में उच्च न्यायालय को रिट याचिका को निष्फल मानने का निर्देश देने के अलावा और कुछ नहीं करने की जरूरत है। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। इस आदेश के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना का नोटिस और अवमानना कार्यवाही रद्द की जाती है।

आर.पी.

अपीलें स्वीकार की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।